



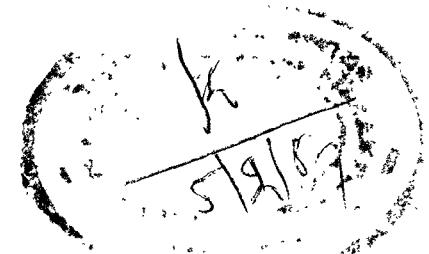
# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 566]

मई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 5, 1986/अग्रहायण 14, 1908

No. 566] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 5, 1986/AGRAHAYANA 14, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

कार्मिक और लोक शिकायत तथा पेशन न्यायालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

मई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 1986

सा.का.नि. 1253(ग्र).—केंद्रीय सरकार प्रशासनिक अधिकरण  
अधिनियम, 1985 (1985 का 13) के द्वारा 35 का उपचारा (2)  
के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित  
नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संवित नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संवित नाम  
मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के  
बेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1986 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिचाला.—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अनिवार्य  
न हो:—

(क) "अधिनियम" से प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985  
(1985 का 13) अनिवार्य है।

(ख) "सरकार" से मध्य प्रदेश सरकार अनिवार्य है।

(ग) "अधिकर" से मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण अनिवार्य है।

(घ) इन नियमों में जो शब्द तथा अभिव्यक्तियां प्रयुक्त की गई हैं  
परन्तु जिन्हें यहां परिचालित नहीं किया गया है और अधिनियम  
में परिचालित किया गया है उनका अर्थ क्रमशः वहां होगा जो  
अधिनियम में दिया गया है।

3. बेतन.—(1) अध्यक्ष तंत्र हजार पाँच सौ रुपए का बेतन और  
ठाई सौ रुपए का विशेष बेतन प्रति मास प्राप्त करेगा। उपाध्यक्ष छाँड  
हजार पाँच सौ रुपए का बेतन प्रति मास प्राप्त करेगा। सदस्य तंत्र हजार  
रुपए प्रति मास का बेतन प्राप्त करेगा।

परन्तु किसे ऐसे व्यक्ति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में  
नियुक्त की जिसमें जो किसी उच्च न्यायालय के स्वायार्थ जैसे सेवा  
निवृति हुआ है या जो केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार से  
हुआ है आ जो पेशन या उपायान या दोनों या अधिकारी अधिकार विभिन्न  
नियोजक के अधिदाय के रूप में कोई सेवा निवृति फालदे या अध्य  
प्रकार के सेवानिवृत्ति फालदे प्राप्त कर रहा है या कर चुका है या अप्राप्त  
करने का हकदार हो गया है तो पूर्वोक्त बेतन में से उसके द्वारा प्राप्त या  
प्राप्त की जाने वाले पेशन और उपायान की समतुल्य पेशन या अधिदायों  
भविष्य निधि में नियोजक के अधिदाय या किसी अध्य प्रकार के सेवा  
निवृत्ति दायरों, यदि कोई हो, क. कुल रकम कम कर दी जाएगी।

4. महांगाई भत्ता और नगर प्रतिकरात्मक भत्ता—अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या और कोई सदस्य उस दरों पर महांगाई भत्ता और नगर भत्ता प्रतिकरात्मक भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा जो केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों को वेतन की समान दरों पर अनुज्ञेय है।

5. सदस्य के रूप में नियुक्ति पर मूल सेवा से सेवानिवृत्ति—(1) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या कोई सदस्य जो अधिकरण में अपनी नियुक्ति को सारीक को, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन सेवा में का, अधिकरण में अपनी नियुक्ति के पूर्व ऐसी सेवा से निवृत्ति ले लेगा। किसी उच्च न्यायालय के किसी ऐसे आसेन न्यायाधीश की दशा में जिसे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, अधिकरण में उसकी सेवा संविधान के द्वारा अनुसूचि के भाग (ब) के पैरा ii(ख) (i) के अन्तर्गत बास्तविक सेवा मानी जाएगी।

(2) उपनियम (1) में यथा उपबन्धित सेवा निवृत्ति पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा कोई सदस्य—

(i) उसकी लागू सेवा निवृत्ति प्रसुविधाओं से संबंधित नियमों के अनुसार पेशन और उपदान प्राप्त करने का हकदार होगा,

(ii) उपाजित छुट्टी अन्तर्गत करने के लिए अन्तर्गत नहीं होगा किन्तु अपनी सेवा निवृत्ति के पूर्व उसके लागू नियमों के छुट्टी सम्बलम् यदि कोई हो, के समतुल्य नकद रकम प्राप्त करने का हकदार होगा।

6. छुट्टी—(1) अधिकरण में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी सदस्य के रूप में नियुक्ति पर कोई व्यक्ति निम्नलिखित रूप में छुट्टी प्राप्त करने का हकदार होगा।

(i) सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष या उसके किसी भाग के लिए पन्द्रह दिनों की दर दर उपाजित छुट्टी;

(ii) सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष की बावत बीस दिन की दर पर चिकित्सा प्रमाणपत्र या निजी काम के आधार पर आवा बेतन छुट्टी। आवा बेतन छुट्टी के लिए सम्बलम् उपाजित छुट्टी के दीरान अनुज्ञेय छुट्टी सम्बलम् के आधार के समतुल्य होगा;

(iii) सदस्य के चिकित्सानुसार आधार बेतन पर छुट्टी को पूरे बेतन अद्वितीय में परिवर्तित किया जा सकता है परन्तु वह चिकित्सा आधारों पर ली गई हो और सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी के चिकित्सा प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित की गई हो;

(iv) पद की एक अवधि में एक सौ अस्सी दिनों की अधिकतम कालावधि तक बेतन और भत्ते के बिना असाधारण छुट्टी।

(2) यदि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य अधिकरण के साथ अपनी कार्य व्यवस्था के कारण पूर्ण श्रावकाश का उपभोग करने में असमर्थ है, तो वह प्रावकाश की अनुपायुक्त कालावधि को छुट्टी के लेखे में जोड़ने का हकदार होगा।

स्पष्टीकरण : इस उपनियम के प्रयोजन के लिए "प्रावकाश" से अधिकरण द्वारा माने जाने वाले प्रत्येक कलेंडर वर्ष में तास दिन की श्रावकाश अनुभित है।

(3) अधिकरण में अपने पदावधि की समाप्ति पर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य अपने नाम में जमा उपाजित छुट्टी की बावत छुट्टी सम्बलम् के समतुल्य नकद प्राप्त करने का हकदार होगा, परन्तु इस उपनियम और नियम 5 के उपनियम (2)(ii) के अन्तर्गत छुट्टी की मात्रा जिसकी नकद रकम प्राप्त की गई है एक सौ अस्सी दिनों से अधिक नहीं होगी।

(4) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य अधिकरण से पदमुक्त होने को सारीक को प्रवृत्त दरों पर उपनियम (3) के अन्तर्गत यथा-अनुज्ञेय छुट्टी सम्बलम् पर महांगाई भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे।

परन्तु वह ऐसे छुट्टी बेतन पर नगर प्रतिकरात्मक भत्ते या किसी अन्य भत्ते का हकदार नहीं होगा।

7. छुट्टी भंजूर करने वाला प्राधिकारी—किसी सदस्य और उपाध्यक्ष को छुट्टी भंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष को छुट्टी भंजूर करने के लिए मध्य प्रदेश का राज्यपाल सक्षम प्राधिकारी होगा।

8. पेंशन—(1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी राज्य के रूप में अधिकरण में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति पेंशन का हकदार होगा, परन्तु ऐसी पेंशन देय नहीं होगी,--

- (i) यदि उसने अधिकरण में दो वर्ष से कम सेवा की है; या
- (ii) यदि उसे अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन अधिकरण में किसी पद से हटाया गया है।

(2) उपनियम (1) के अन्तर्गत पेंशन प्रत्येक पूरे सेवा वर्ष या उसके किसी भाग के लिए सात सौ रुपए प्रति वर्ष की दर पर संगति की जाएगी और अधिकरण में सेवा वर्ष की संख्या पर ध्यान दिए बिना, पेंशन की अधिकतम रकम 3,500/- रुपए प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी।

परन्तु इस नियम के अधीन देय पेंशन को कुल रकम ऐसी पेंशन जिसके अन्तर्गत संराशकृत पेंशन का भाग, यदि कोई भा. रकम सहित, जो अधिकरण में पद धारण करते तथा प्राप्ति के गई है, या जिसको प्राप्त करने के लिए हकदार है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए विनियिष्ट पेंशन की अधिकतम रकम से अधिक नहीं होगी।

9. अधिष्ठ निधि—अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य अधिष्ठ निधि में अपने विकल्प पर अभिदाय करने का ही हकदार होगा और उसके ऐसा विकल्प होने की दशा में मध्य प्रदेश सामान्य (अधिष्ठ निधि) नियमबाबत, 1955 के उपनियमों से आसित होगा;

परन्तु यदि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य अधिकरण में अपना कार्यभार संभालने के ठंक पूर्व किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या अधिक भारतीय सेवा का सदस्य या या केन्द्रीय ग्रन्थालय किसी राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण किए हुए था, तो वह ऐसे नियमों से आसित होगा जो अधिकरण में कार्यभार संभालने के ठंक पूर्व उसको लागू थे।

10. यात्रा भत्ते—अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य दौरे पर या स्थानस्थर (पर) जिसके अन्तर्गत अधिकरण में कार्यभार संभालने के लिए या अधिकरण से उसको पदावधि की सामिति पर स्वनगर जाने के लिए की गई यात्रा भी है) यात्रा भत्तों, दैनिक भत्तों, व्यक्तिगत मात्र अवश्य और अन्य समान चीजों के परिवहन के लिए उसी मापदान और दरों पर जो उच्च न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ते) नियम, 1956 में विनियिष्ट हैं, हकदार होगा।

11. छुट्टी यात्रा रियायत : अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य उन्हों दरों और उन्हीं शर्तों पर छुट्टी यात्रा रियायत का हकदार होगा जो कि उसी बेतनमान में बेतन पांच बाले अधिक भारतीय सेवा के सदस्यों पर लागत है।

12. बास सुविधा : (1) अधीन, उपाध्यक्ष या किसी सदस्य के रूप में अधिकरण में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, सरकार द्वारा समवस्थय पर विहित दरों पर प्रत्यक्षित किस के संगति लिए जाने के लिए उपलब्ध होने के लिए उपलब्ध होने के उपलब्ध होने के लिए निवास स्थान उपलब्ध हो।

(2) जब अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी सदस्य को उपनियम (1) में विनियिष्ट शासकीय निवास उपलब्ध नहीं कराया जाता है या वह उसका उपयोग नहीं करता है तो उसे उसके बेतन के पन्द्रह प्रतिशत के बराबर भत्ता प्रतिवास संदत किया जा सकेगा।

(3) जब अध्यक्ष उपाध्यक्ष या कोई मद्य अनुदेश अवधि के परे शासकीय निवास का उपयोग करता है तो वह यथासंभव, अतिरिक्त अनुज्ञित फैसला या शास्त्रिक कियाये का संदाय करने का दायी होगा और उसे सरकार के नियमों के अनुसार बेदखल कराया जा सकेगा।

13. सदार्थी मुविधा-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य सरकार के स्टाफ कार नियमों के अनुसार स्टाफ कार मुविधा का हकदार होगा ।

14. चिकित्सा उपचार की मुविधाएं—अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य चिकित्सा उपचार और अस्पताल मुविधाओं का उसी प्रकार हकदार होगा जिस प्रकार सरकार के अध.न उनके बराबर मापदानां ज्वाल भारतीय प्रशासनिक सेवा के किसी सदस्य को अनुज्ञय है ।

15. अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त उच्च न्यायालय के आसीन न्यायाधीशों की सेवा की शर्तें इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी जहाँ किसी उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश अधिकरण के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है तो उस पर, उच्च न्यायालय के आसीन न्यायाधीश के रूप में उसकी विविवरिति की तारीख तक, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 और उसके अधीन बनाए गए नियमों में यथा अन्तविष्ट सेवा शर्तें लागू होंगी । उसके बाद वह अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में, जैसा भी मामला हो, अपने कार्यकाल को शेष अवधि के लिए इन नियमों द्वारा आवित होगा ।

16. अवधिव्यापी उपबंध: अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी सदस्य को सेवा नहीं, जिनके लिए इन नियमों में कोई अविवरित उपबंध नहीं है, भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए अधिकारियों, दिनहां कि वेतन उनके बराबर है, पर उस समय लागू नियमों और आदेशों द्वारा अवधारित की जाएंगी ।

17. नियमों को विधिल करने की शक्ति: केंद्रीय वराहार को, जिसके लिए जाने वाले कार्यों से, इन नियमों के किन्हीं उपबंधों को किसी वर्ग या ग्रन्थी के व्यक्तियों की बाबत विधिल करने की शक्ति होगी ।

[सं. ए-11019/90/85-ए.टी.]

एव. के. पार्श्वार्थी, संयुक्त सचिव

### MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 5th December, 1986

G.S.R. 1253(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of section 35 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

(1) Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Services of Chairman, Vice Chairman and Members) Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires :—

- (a) "Act" means the Administrative Tribunals Act 1985 (13 of 1985) ;
- (b) "Government" means the Government of Madhya Pradesh ;
- (c) "Tribunal" means the Madhya Pradesh Administrative Tribunal ;
- (d) the words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Pay.—(1) The Chairman shall receive a pay of rupees three thousand five hundred plus a special pay of rupees two hundred fifty per mensem. A Vice-Chairman shall receive a pay of rupees three thousand five hundred per mensem. A member shall receive a pay of rupees three thousand per mensem.

Provided that in the case of an appointment as Chairman, a Vice-Chairman or a member of a person who has retired as a judge of a High Court or who has retired from service under the Central Government or a State Government and who is in receipt of or has received or has become entitled to receive any retirement benefits by way of either pension or gratuity or both or employer's contribution to the Contributory Provident Fund or other forms of retirement benefits, the aforementioned pay shall be reduced by the gross amount of pension and pension equivalent of gratuity or employer's contribution to the Contributory Provident Fund or any other form of retirement benefits, if any, drawn or to be drawn by him.

4. Dearness allowance and city compensatory allowance.—The Chairman, a Vice-Chairman and a Member shall receive dearness allowance and city compensatory allowance admissible to the Officers of the Central Government getting the same rates of pay.

5. Retirement from parent service on appointment as member.—(1) The Chairman, a Vice-Chairman or a Member who, on the date of his appointment, to the Tribunal, was in service under the Central Government or a State Government, shall seek retirement from such service before his appointment to the Tribunal. In the case of a sitting Judge of a High Court who is appointed as Chairman or a Vice Chairman, his services in the Tribunal shall be treated as actual service within the meaning of para 11(b)(i) of part 'D' of the Second Schedule to the Constitution.

(2) On such retirement as is provided for in sub-rule (1), the Chairman, a Vice-Chairman or a Member :—

(i) shall be entitled to receive pension and gratuity in accordance with the rules relating to the retirement benefits applicable to him,

(ii) shall not be allowed to carry forward earned leave but shall be entitled to receive cash equivalent to leave salary, if any, in accordance with the rules applicable to him prior to his retirement.

6. Leave.—(1) A person, on appointment to the Tribunal as Chairman, a Vice-Chairman or a Member shall be entitled to leave as follows :

(i) earned leave at the rate of fifteen days for every completed year of service or a part thereof;

(ii) half pay leave on medical certificate or on private affairs at the rate of twenty days in respect of each completed year of service. The leave salary for half pay leave shall be equivalent to half of the leave salary admissible during the earned leave ;

(iii) leave on half pay can be commuted to full pay leave at the discretion of the individual provided it is taken on medical grounds and is supported by a medical certificate from the competent medical authority.

(iv) extra-ordinary leave without pay and allowances upto a maximum period of one hundred eighty days in one term of office.

(2) If the Chairman, a Vice-Chairman or a Member is unable to enjoy full vacation on account of his occupation with the Tribunal, he shall be entitled to add the unenjoyed period of vacation to the leave account.

Explanation.—For the purpose of this sub-rule, "vacation" means vacation of thirty days in each calendar year observed by the Tribunal.

(3) On the expiry of his term of office in the Tribunal, the Chairman, a Vice-Chairman or a Member shall be entitled to receive cash equivalent of leave salary in respect of the earned leave standing to his credit provided that the quantum of leave encashed under this sub-rule and sub-rule (2)(ii) of rule 5 shall not exceed 180 days.

(4) The Chairman, a Vice Chairman and Member shall be entitled to receive the dearness allowance on the leave salary under sub-rule (3) as admissible at the rates in force on the date of the relinquishment of the office in the Tribunal.

Provided that he shall not be entitled for the city compensatory allowance or any other allowance on such leave salary.

7. Leave sanctioning authority.—The Chairman shall be the authority competent to sanction leave to the Member and the Vice Chairman. The Governor of Madhya Pradesh shall be the authority competent to sanction leave to the Chairman.

8. Pension.—(1) Every person appointed to the Tribunal as the Chairman or a Member shall be entitled to pension provided that no such pension shall be payable;

(i) if he has put in less than two years of service with the Tribunal;

or

(ii) if he has been removed from an office in the Tribunal under sub-section (2) of Section 9 of the Act.

(2) Pension under sub-rule (1) shall be calculated at the rate of rupees seven hundred per annum for each completed year of service or a part thereof and irrespective of the member of years of service in the Tribunal, the maximum amount of pension shall not exceed rupees three thousand five hundred per annum.

Provided that the aggregate amount of pension payable under this rule together with the amount of any pension including commuted portion of pension, if any, drawn or entitled to be drawn while holding office in the Tribunal shall not exceed the maximum amount of pension specified for a judge of the High Court.

9. Provident Fund.—The Chairman, a Vice-Chairman or a Member shall be entitled to subscribe to the Provident Fund at his option and in case of his so opting shall be governed by the provisions of the Madhya Pradesh General (Provident Fund) Rules, 1955.

Provided that if the Chairman, a Vice Chairman or a Member was a Judge of a High Court or was a Member of an All India Service or was holding a post under the Central or a State Government immediately before his joining the Tribunal, he shall be governed by the rules which were applicable to him immediately before joining the Tribunal.

10. Travelling Allowances.—The Chairman, a Vice-Chairman or a Member while on tour or on transfer (including the journey undertaken to join the Tribunal or on the expiry of his term with the Tribunal to proceed to his home town) shall be entitled to the travelling allowance, daily al-

lowance, transportation of personal effects and other similar matters at the same scales and at the same rates as are prescribed in the High Court Judges (Travelling Allowances) Rules, 1956.

11. Leave Travel Concession.—The Chairman, a Vice-Chairman or a Member shall be entitled to the leave travel concession at the same rates and the same scales and on the same conditions as are applicable to the members of the All India Services drawing pay at the same rates.

12. Accommodation.—(1) Every person appointed to the Tribunal as Chairman, a Vice Chairman or a Member shall be entitled to the use of official residence of appropriate type, subject to availability, on the payment of licence fee at the rates prescribed by Government from time to time.

(2) When the Chairman, Vice Chairman or a Member is not provided with or does not avail himself of the official residence referred to in sub-rule (1), he may be paid every month an allowance of an amount equal to fifteen per cent of his pay.

(3) Where the Chairman, Vice Chairman or a Member occupies an official residence beyond the permissible period he shall be liable to pay additional licence fee or penal rent, as the case may be, and liable to eviction in accordance with the rules of the Government.

13. Facility of conveyance.—The Chairman, a Vice Chairman or a Member shall be entitled to the facility of staff car in accordance with the Staff Car Rules of the Government.

14. Facilities for Medical Treatment.—The Chairman, a Vice Chairman and a Member shall be entitled to medical treatment and hospital facilities as are admissible to a member of the Indian Administrative Service of the corresponding pay levels in the Government.

15. Conditions of service of sitting judges of the High Court appointed as Chairman or Vice-Chairman.—Notwithstanding anything contained in these rules, where a sitting judge of a High Court is appointed as the Chairman or a Vice-Chairman of the Tribunal, the service conditions as contained in the High Court Judges (Conditions of Service) Act, 1954 and the rules made thereunder shall apply to him, upto the date of his superannuation as a sitting judge of the High Court. Thereafter he shall be governed by these rules for the remaining period of his tenure as Chairman or Vice Chairman, as the case may be.

16. Residuary provision.—The conditions of service of the Chairman, a Vice Chairman or a Member for which no express provision is available in these rules shall be determined by the rules and orders for the time being applicable to officers of corresponding pay levels belonging to the Indian Administrative Service.

17. Powers to relax rules.—The Central Government may, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.

[No. A-11019/90/85-AT]

S. K. PARTHASARATHY, Jt Secy.